



ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षा के पुनर्गठन हेतु विचार

डॉ. रेखा शुक्ला

कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा, प्रतापगढ़

राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Email: rs5117221@gmail.com

Communicated : 20.06.2026

Revision : 20.07.2026
Accepted : 12.08.2026

Published: 30.09.2026

सारांश :

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में एक है। सभी को उच्च शिक्षा सुलभ हो, समान अवसर उपलब्ध कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। (शिक्षा मंत्रालय 2016) जहां विकसित देशों में कम संस्थानों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाता है और एक ही संस्थान से हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं वहीं भारत में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के बिना भी हजारों कॉलेज चल रहे हैं। (तिलक)हां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। निजी संस्थान कागज पर तो खोल दिए गए हैं लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा सुविधाओं का अभाव है। यह सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय प्रयोगशालाओं का अभाव, शिक्षकों की योग्यता एवं संख्या से संबंधित है। (जयपुर, रिसर्च पब्लिकेशन) परिणाम यह है कि मोटी फीस देकर इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त लाखों युवा बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े हैं और जीविकोपार्जन के लिए साधारण आय पर नौकरी ज्वाइन कर बेरोजगारी के शिकार हैं। (वित्त, मंत्रालय भारत सरकार 2019) वर्तमान समय में बहुत से स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के पास ना अपने विषय की जानकारी है ना ही कोई निश्चित उद्देश्य है इसलिए उच्च शिक्षा अव्यावहारिक एवं व्यर्थ सिद्ध हो रही है। ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए नई-नई तकनीक का उपयोग (डिजिटल लर्निंग) स्थानीय (क्षेत्रीय) जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण, उद्योग शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे सुझाव महत्वपूर्ण हैं। (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2020) जिसमें सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे छात्रों की पहुंच बढ़े। कौशल आधारित पाठ्यक्रम जैसे स्थानीय कृषि, हस्तशिल्प और रोजगार परक शिक्षा से युक्त पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे शहरी ग्रामीण खाई को पाटा या कम किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे भवन फर्नीचर इंटरनेट की व्यवस्था करना, दूरस्थ शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा को समावेशी बनाना ताकि सामाजिक आर्थिक बढ़ाएं दूर हो सके। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करके उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना। देश का 70% हिस्सा अभी भी ग्रामीण बना हुआ है जागरूकता का अभाव और राष्ट्रीयता की कमी के कारण उन्हें विकास के बारे में जानकारी नहीं है। कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, उत्कृष्ट शोध, औद्योगिक मूल्यांकन और एथलेटिक कौशल के माध्यम से इस दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने से यह सुनिश्चित होगा कि उसे शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय प्रगति और वैश्विक प्रतिभा का वाहक बन सकेंगी।

प्रमुख शब्द- पुनर्गठन, जीविकोपार्जन, प्रशिक्षित रोजगार परक, पुनर्जीवित, वैश्विक.

प्रस्तावना :

आज के तेजी से वैश्वीकरण और विकास के दौर में भारत में उच्च शिक्षा का बहुत महत्व है यह विद्यार्थियों को अनंत ज्ञान आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करती हैं। (सिंह आर०पी० 2010) जिससे वे सार्थक कैरियर बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त या निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने भौतिक और सामाजिक

परिवेश में बदलाव लाने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है **डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि -** शिक्षा एक मूलभूत मानवाधिकार के साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कुंजी है इसके महत्व के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता कई दशकों से चिंता का विषय रही है भारत जैसे देश में जहां सामाजिक आर्थिक असमान्यताएं व्याप्त हैं उच्च शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन सकती है उच्च शिक्षा पर

जोर देने से विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई को पटाने में मदद मिल सकती है जिसे सभी को सफलता के अधिक समान अवसर प्राप्त हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में देखा गया है कि शहरों में रहने वाले छात्रों की शिक्षा से बहुत अलग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश छात्रों के आसपास उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय विश्वविद्यालय न होना अपर्याप्त प्रशिक्षण वाले शिक्षक और पर्याप्त किताबें अथवा पुस्तकालय न होने जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2016 वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग)

भारत विश्व के सबसे युवा देश में से एक है उच्च शिक्षा पर जोर देते हुए अनेक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतीय प्रबंधन संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(RUSA) नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य नए संस्थानों को खोलना पुराने संस्थाओं में सुधार करने और सुलभता समानता और उत्कृष्ट को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने की सहायता करता है। (शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2016) वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तकनीकी और सांस्कृतिक उथलपुथल के कगार- पर खड़े हैं उच्च शिक्षा की आवश्यकता पहले से अधिक है लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें घटते नामांकन बेतहाशा बढ़ती लागत और आम जनता की खराब धारणा शामिल है। जिसके परिणाम स्वरूप कितने उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है कई संस्थाओं के लिए अपनी वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने का एकमात्र तरीका अपनी रणनीति को पुनर्गठित करना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियों का पुनर्गठन निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है -

1- शिक्षा में सार्वजनिक निवेश और वित्तीय पोषण को बढ़ाना -

शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को धीरेधीरे सकल घरेलू - उत्पाद के काम से कम 6% तक बढ़ाना चाहिए जिससे स्कूल के बुनियादी अवसंरचना, शिक्षकों की भर्ती और

प्रशिक्षण पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित किया जाए। राज्यों को सरकारी महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों स्वच्छता सुविधाओं और डिजिटल कक्षाओं को अनंत बनाने के लिए परिणाम आधारित एवं आवश्यकता आधारित अनुदान प्रदान करने की शुरुआत करना चाहिए

2 - उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए अभिगम्यता और समावेशन में सुधार करना - निम्न सकल नामांकन अनुपात(GER) वाले राज्यों में लक्षित केंद्रीय सहायता के माध्यम से सार्वजनिक विश्वविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय का विस्तार किया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति परिवहन सुविधाएँ और डिजिटल पहुंच को मजबूत करना होगा

3 - परिवारों पर वित्तीय भोज कम करना और शिक्षा को एक सार्वजनिक हित के रूप में पुनः स्थापित करना, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करके निजी संस्थाओं की ओर बाध्य पलायन को कम किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि को रोकने और अभिभावकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु शुल्क विनिमयन समिति के मॉडल का अनुसरण कर सकती है।

4- बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी में सुधार करना- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार के निजी क्षेत्र और समुदायों के संयुक्त प्रयासों से इसमें सुधार हो रहा है। कई ग्रामीण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण कक्षाओं प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की कमी है। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी ग्रामीण उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अनुपयुक्त भवन और दूरस्थ संस्थानों में छात्रों की पहुंच को सीमित करते हैं, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही कठिन चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जाय, जिससे दूर दराज के छात्र भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

“विश्वविद्यालय असल में पुस्तकालय के चारों ओर भावनाओं का समूह है” अमेरिका लेखक सेल्वी फुट का यह विचार वाकई अद्भुत है। अच्छी शिक्षा और शिक्षण की नींव सुदृढ़ बुनियादी ढांचे पर ही रखी जा सकती है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्च शिक्षा संस्थानों के कक्षा गृह और आंतरिक साज , सजा का विद्यार्थियों के विकास पर ,अधिगम पर गहरा प्रभाव डालता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों में भवनो का अनुचित लेआउट कक्षाओं के अंदर वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश की कमी खराब रखरखाव वाला फर्नीचर, अस्त व्यस्त प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय हैं। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

भौतिक बुनियादी ढाँचे की कमी की भारपाई के लिए, डिजिटल कक्षाओं, दूरस्थ विशेषज्ञ -नेतृत्व वाले निर्देश -आधुनिक शिक्षण और ए आर वी आर उपकरणों जैसी विधियों को लागू किया जा सकता है। मानकीकृत और दूरदराज के क्षेत्रों में भी कैरियर - आकलन सुनिश्चित करने के लिए समान आकार के -मार्गदर्शन डिजिटल बुनियादी ढाँचे की भी आवश्यकता होगी (नंदी, ए. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० चुनौतियाँ और -अवसर" (ऑनलाइन)

दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना

शिक्षा समाज का दर्पण है। भारत के अधिकांश आबादी गांव में बसती है किसानों का मुख्य स्रोत कृषि है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का एक तरीका है जो सीखने के ढंग को बताता है। यह प्रभावी ढंग से सभी परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान कर औपचारिक प्रणाली को पूरक बन सकती है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन में दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करती है** लागत प्रभावी है तथा नवाचार आत्मक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है।

विश्व विद्यालय की स्थापना

मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करके दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा एवं साक्षरता की दर में वृद्धि किया जा सकता है इस उद्देश्य की पूर्ति में विश्वविद्यालय ग्रंथालय को महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में माना जा सकता है।

व्यावसायिक शिक्षा और जीवन कौशल का विकास करना गांव में उच्च शिक्षा के प्रचार से ही हम एक नए

भारत की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय गांव में शिक्षा के प्रसार से ही गरीबी से मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। गांव में बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने से छात्रों को आर्थिक विकास मिलेगा और उनकी सोच में बदलाव आएगा। यह उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका देता है जिससे वह स्वयं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के माध्यम से समाज में सामाजिक कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा में कृषि एवं गैर सरकारी कृषि क्षेत्र में रोजगार के आधिकारिक अवसर निर्मित होने चाहिए। आधिकाधिक ग्रामीण विद्यार्थियों को कौशल कार्यक्रम विकास से प्रशिक्षण देना चाहिए। युवाओं को कौशल विकास के लिए आगे आने के लिए नामांकन देना होगा। **कोठारी आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को काम और व्यावहारिक कौशल से जोड़ा जाना चाहिए। व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थानीय उद्योगों कारीगरों और कौशल विकास संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाना चाहिए।**

उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना

भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के भीतर एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विश्वविद्यालय में अनुसंधान और डाक्टरेट कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक निधि में वृद्धि की जानी चाहिए। उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग एकेडमिक सहयोग और मिशन उन्मुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्टैंड फोर्ड विश्वविद्यालय के स्टार्ट एक्स एवं उद्यमिता कार्यक्रमों जैसे सफल उदाहरण के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय में समर्पित उद्यमिता एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना करके छात्रों शिक्षकों को उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल उद्योगों में बदलने के लिए मार्गदर्शन की पोषण के अवसर तथा सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना :

जहां भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान संयुक्त डिग्री शाखा परिसरों की पेशकश करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहकारिता स्थापित कर सकते हैं। वही इससे वैश्विक संपर्क में वृद्धि हो सकती है ज्ञान हस्तांतरण सुगम बन सकता है और भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापकों की जवाब दे ही स्थापित करने पर जोर दिया है आजकल देश में उच्च शिक्षा की कमियों को दूर कर उसमें गुणवत्ता लाने की चर्चा बड़े जोरों पर है इसके लिए अनेक स्तरों पर तरहतरह के - उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

1 - आज के समय विभिन्न सामरिक और सामाजिक चुनौतियों के उन्मूलन में विज्ञान की प्रभावी भूमिका है उच्च शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवसायिकता की अपेक्षा गुणात्मकता, प्रतिस्पर्धा, समर्पण को महत्व दिया जाना चाहिए

2 - भारत में वैज्ञानिक शोधों पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए वैज्ञानिक शोधों पर होने वाला खर्च एक तरह से निवेश है जिससे हमें कई तरह के प्रतिफल मिलते हैं

3 - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख नंदन नीलेकणी के अनुसार भारत को अपने डेमोग्राफिक लाभांश का फायदा उठाना चाहिए इस समय भारत के लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है

4 - किसी भी संस्थान की सफलता और सफलता शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है हमें इन कड़ियों की भूमिका का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा तभी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आ पाएगा।

5 - इस योजना के अंतर्गत उन सरकारी कॉलेजों को अतिरिक्त धन एवं सुविधाएं दी जाती है जहां प्रोफेसर का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है तथा जहां

प्रोफेसर ठेके पर रखे गए हैं विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अनुदान तब ही मिलना चाहिए जब प्रोफेसर का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा तथा किसी स्वतंत्र बाहरी संस्था द्वारा कराया जाए। (नंदन नीलेकणी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

6 - हर वर्ष लाखों की संख्या में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारक निकलते हैं लेकिन रोजगार पर रखना मात्र 10% है अपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षित युवाओं की दिशा को सही जगह पर ले जाया जाए उन्हें रोजगार परक बनाया जाना जरूरी है।

7- ज्ञान के नवीनतम क्षेत्र के प्रति उत्सुकता ही किसी विश्वविद्यालय को प्रासंगिक बनाए रख सकती है। इसके लिए समय अनुकूल बदलाव आवश्यक है। इसके लिए प्रतिभाशाली विद्वानों, चिंतकों तथा विषय पर गहरी पकड़ रखने वालों को जोड़े रखना चाहिए। रचनात्मक और कल्पनाशील अध्यापकों को अवश्य स्थान देना चाहिए।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग-

आईसीटी उपकरणों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, विश्लेषित करने, उसका आदान प्रदान करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिशन दस्तावेजों के अनुसार आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में एक उपकरण की भांति किया है। जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन की दर जो 15% है उसे 30% करना है। शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण का अत्यधिक महत्व है। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में विद्यार्थियों की योग्यतानुसार पाठ सामग्री को बोधगम्य बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षा में सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका निभाती है। औपचारिक अनौपचारिक सभी तरह की - शिक्षा में महत्व रखती है। इनफॉर्मेशन और

कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त किया है। यह शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाती है। तथा सभी प्रकार के अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में आईसीटी का अत्यधिक महत्व है। (UGC, 2021)

निष्कर्ष :

शिक्षा मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त ज्ञान तथा कौशल विकास के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है। सराहनीय प्रगति के बावजूद भारत की उच्च शिक्षा का सफर असमानताओं से भरा हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, संकाय और अनुसंधान के अवसरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्षेप में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और सुलभता में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ शिक्षा को अधिक समावेशी और वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे की कमियों और शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। भारत में शिक्षा को सही मायने में बदलने के लिए व्यावहारिक शिक्षा, मार्गदर्शन और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन मुद्दों को हल करके भारत अपने युवाओं की क्षमता का सदुपयोग कर सकता है। और एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमें मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदलकर रोजगार परक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो, जिसमें नवीनता और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले। भारत को अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं ही पहल करनी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- एमएचआरडी 2016 एनुअल रिपोर्ट, डिपार्टमेंट आफ हायर एजुकेशन , गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली
- एचएमआरडी 1969 ,नेशनल पॉलिसी आन एजुकेशन 1986,पीआन 1990 ,न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया प्रेस
- सिंह, आर.पी. 2010 आन ओपनिंग ए वर्ड क्लास यूनिवर्सिटी, न्यूज़ नहीं दिल्ली
- विश्वविद्यालय प्रबंधन व शिक्षा की समस्याएं जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन
- तिलक जांदला हायर एजुकेशन इन इंडिया फंडिंग एक्सेस क्वालिटी का इक्विटी नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2025 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
- आर्थिक समीक्षा 2018-19 वित्त मंत्रालय भारत सरकार
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1986 10-शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
- नंदी, ए. "राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० -चुनौतियाँ और अवसर" (ऑनलाइन)<http://www.ijPmr.com>.
- प्रो. अरुण. सी. मेहता." भारत में परिवारों के लिए बढ़ती शिक्षा लागत की चुनौती 2023 Education For All in India.com.
- डॉ० अर्जुन सिंह बघेल " मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में व्यावसायिक उद्यमों की चुनौतियाँ
- जर्नल ऑफ़ एडवांसेज एण्ड स्कॉलरशिप रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन में प्रकाशित, ई- आई एस एस एन : 2230-7540 खंड-14 अंक संख्या २, जनवरी 2018
- University Grant Commission (2021)
- Higher Education statistics. <https://www.ugc.ac.in>